subsidy on (50 : 50) basis. No other proposal for grants-in-aid to voluntary agencies for identification and rehabilitation of bonded labour has been received. The scheme has since been transferred to the States.

In addition to managerial subsidy @ Rs. 5,000 per annum, the scheme also provides for payment at the rate of Rs. 100 for each release order in excess of 20 secured in a year subject to a maximum of Rs. 10,000 in a year inclusive of managerial subsidy. During the last three years, no proposals have been received from any Voluntary Organisation through the State Governments or Council for Advancement of Peoples' Action and Rural Technology (CAPART) in this respect. There is also a provision that CAPART will first spend from its resources the Central Share to be given to the Voluntary Agencies concerned and then claim for reimbursement. No such claim for reimbursement has been received either from CAPART during the last 3 years ending 31-3-1993.

Collaboration with China in Coal Technology

*269. Shri CHIMANBHAI MEHTA :
DR. SANJAYA SINH :

Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether serious attempts are in motion to work out a co-operation with China in coal technology sector; if so, the details thereof;

(b) what are the major variations in Indian and Chinese technologies in the coal sector and details of benefit India will get from Chinese co-operation; and

(c) what are the figures of coal production in India and China per annum in various categories of coal ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) to (c) A delegation led by Secretary, Ministry of Coal visited China in June, 93 under a UNIDO sponsored technical exchange programme. During discussions held with the Chinese authorities, there were positive indications of fruitful co-operation in the field of coal industry between India and China. As a follow-up a technical group comprising of experts from Coal India Limited & Singareni Collieries Company Ltd. have gone to China to indentify the areas of possible co-operation, particularly in the field of underground mechanised longwall technology and coal utilisation related areas.

China's reported coal production during 1992-93 was about 1140 million tonnes with 95% contribution by Underground mining and only 5% coming from Surface mining. In India, out of a coal production of 240 million tonnes during 1992-93, about 2/3rd of the production came from Surface mining and only 1/3rd from Underground mining. In the event of a co-operation between both the countries, the Indian Coal Industry could take advantage of Chinese experience to boost its coal production from Underground mining. India could also be benefited in procurement of Chinese made Longwall equipment which are reported to be much cheaper than the European countries from where India is presently importing the equipment.

In terms of type of coal being mined in China and India *per annum, the raw coal production* figure available for the year 1991 are as follows :

Chinese Raw Coal Production by Coal type in 1991

		China	India
	Type	Output(MT)	Output(MT)
1.	Anthracite	229.77	—
2.	Bituminous	845.15	229.28

भूमिगत कोयला खनन की नई तकनीक का विकास

*270. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 1974-75 की अपेक्षा 1992-93 के वर्ष के दौरान भूमिगत कोयला खनन में कमी आई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयला उद्योग के लिए शोध एवं अन्वेषण कार्य में संलग्न संस्थानों द्वारा इस अवधि के दौरान भूमिगत खनन हेतु एक नई तकनीक का भी विकास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार अब इस प्रयोजन के लिए चीन से तकनीक लेने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस तकनीक को अपनाने के बाद कोयला उत्पादकता व खनन लागत के बारे में अनुमान क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं । कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० की भूमिगत खानों द्वारा कोयले का उत्पादन वर्ष 1974-75 में 64.30 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 1992-93 में 70.36 मिलियन टन किया गया ।

(ग) और (घ) यद्यपि भारत में अनुसंधान संस्थानों द्वारा किसी विशेष खनन प्रौद्योगिकी को विकसित नहीं किया गया है, अनेक प्रमुख कोयला उत्पादक देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, यू० के०, पोलैंड तथा रूस से सहायता लेकर 1974—93 की अवधि के दौरान कई नई भूमिगत खनन प्रौद्योगिकियों को आरंभ किया गया है । इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियां निम्न है : पावर स्पोर्ट उपकरण के इस्तेमाल से यांत्रिकृत लांगवाल माइनिंग तथा सब-लेवल केविंग; गैलरी ब्लास्टिंग पद्धति; साइड डिस्चार्ज लोडर (एस० डी० एल०) तथा लोड हाल डम्पर्स (एल० एच० डी०) के इस्तेमाल द्वारा यांत्रिकृत बोर्ड तथा पिल्लर; डिसैंडिंग शील्ड माइनिंग, आदि ।

(ङ) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० के अधिकारियों का एक तकनीकी दल चीन की यात्रा पर गया है, ताकि कठिन तथा विस्तृत सैंडस्टोन स्थितियों में, जैसी कि कुछ हमारी खानों में भी व्याप्त हैं, भूमिगत लांगवाल मुहानों में छत के प्रबंधन संबंधी चीन की प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन किया जा सके ।

(च) इसमें अन्तर्ग्रस्त लागत तथा प्राप्त की जाने वाली संभावित उत्पादकता का अभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है ।

Implementation of 'No Work, No Pay' Policy

*271. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some State Governments are implementing the policy of "no work, no pay" in respect of Government, public sector and local self Government employees of such States;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government proposes to apply the policy at the national level in the near future; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) "No work, no pay" is already the general policy of the Government of India also.

कोयले के बढ़ते मूल्यों का असर

*272. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1991 से देश में कोयले की कीमतों में लगभग 48% वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप बिजली उत्पादन और इस्पात उत्पादन में क्रमशः रू० 1.27 प्रति के०डब्ल्यू०एच० और रू० 61.00 प्रति टन की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्रमशः मार्च, 1992 और मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान देश में कोयला उद्योग ने लाभ कमाया है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान कितना-कितना लाभ कमाया गया;

(ङ) क्या इन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन की लागत में भी कमी आई है, यदि हां, तो प्रतिवर्ष उसमें अनुमानतः कितनी कमी आई है; और

(च) देश में कोयला खनन उद्योग में कुल कितनी पूंजी का निवेश हुआ है तथा इसमें विदेशी पूंजी कितनी है और कर्ज ली गई राशि कितनी है तथा कर्ज पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया जाता है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1991 के बाद से कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतों में निम्नलिखित वृद्धि प्रभावी की गई है :—

कंपनी	तारीख जब से प्रभावी हुई	औसत कीमत प्रति मि० टन		प्रतिशतता में वृद्धि
		वृद्धि से पूर्व	वृद्धि के बाद	
को०इं०लि०	17-2-93	322*	364	13.04
	19-6-93	364	382	4.9
सिं०को०कं०लि०	17-2-93	388*	434	11.85
	19-6-93	434	452	4.15

(* दिसम्बर, 1991 में निर्धारित की गई कीमतें)

दिसम्बर, 1991 से जून, 1993 तक वृद्धि प्रतिशतता, कोल इंडिया लि० (को०इं० लि०) के मामले में 18.6% और सिंगरेनी